the financial year 1984-85 is as under:

(*Rs. in crores*)

Year	*Value of exports/target*
1984-85 (Estimated)	794.47

Since the chemicals and allied products sector includes a very large number of items which do not have a uniform unit of measurement, it is difficult to indicate the quantum of exports in physical terms.

(b) Export of chemicals and allied products is expected to increase during the current financial year. The value and quantum of exports will depend upon the demand in the international market. These items are being exported mainly to USSR, USA, UK, UAE, Japan, W. Germany, Aden, France, Singapore, Nigeria, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Muscat and Oman.

Raising of service charges by Banks

1861. SHRI R. SAMBASIVA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the nationalised banks have recently raised their service charges especially for large and medium borrowers; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) According to information available with the Reserve Bank of India eight nationalised banks and State Bank of India and its subsidiaries have revised their charges for services rendered by them to customers including large and medium borrowers. The revisions have been effected taking into consideration the escalation in operational cost and consequential need for rationalisation of service charges.

काले धन संबंधी प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

1862. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर ढांचे और अर्थ-व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण ही मुख्य रूप से काले धन की समस्या के लिए जिम्मेदार है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इसे प्रतिवेदन में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिए गए हैं जिससे कि इस बात की समस्या को हल किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अवैध अर्थ-व्यवस्था के मुख्य-मुख्य कारण जैसा कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की रिपोर्ट में पता लगाए गए हैं, ये हैं—कराधान की ऊंची दरें, आर्थिक नियंत्रणों की सीमा और उनकी पेचीदगी, सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में हेराफेरी नैतिक स्तर में आम गिरावट, मुद्रा स्फीति तथा कर अपवंचन के विरुद्ध निवारक कार्यवाही का कम कारगर होना। यह रिपोर्ट समाचार-पत्रों को रिलीज कर दी गयी है ताकि इस विषय पर सार्वजनिक विचार विमर्श को प्रोत्साहन दिया जा सके तथा उसके परिणामतः प्राप्त होने वाले सुझावों को दीर्घावधिक वित्तीय नीति तैयार करने में इस्तेमाल में लाया जा सके।

Performance and Productivity of Public Sector

1863. SHRIMATI MONIKA DAS: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the newly elected Executive Board of the Standing